

जांच में खुलासा | जिस्म की मंडी में परोसी गई, होटल में एक साथ पहुंचाई जाती थी चार-चार लड़कियां

मुजफ्फरपुर के होटल में भेजी जाती थी बालिका गृह की लड़कियां, खुल रहे राज

भासकर न्यूज | पटना

मुजफ्फरपुर बालिका गृह की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा भी होता था। लड़कियों को जिस्म की मंडी में जबरन परोसा व बेचा गया। डिमांड के आधार पर बालिका गृह से बाहर लड़कियों की सप्लाई की जाती थी। इस कड़ी में लड़कियों को होटल भी भेजा जाता था। ना-नुकुर करने पर जुल्म ढाया जाता था। संचालक ब्रजेश ठाकुर के साथ ही उसके गुर्गे आतंकित करते थे। ये खुलासा पीड़ित लड़कियों ने किया है। एक पीड़िता ने कहा कि उसे कई बार बालिका गृह के बाहर गलत काम के लिए भेजा जाता था। वहां पहले से लोग मौजूद रहते थे। संचालक ब्रजेश या उसके गुर्गे मुजफ्फरपुर के एक होटल में अक्सर लड़कियों को ले जाते थे। वहां दूसरों के हवाले कर दिया जाता था। फिर बंद कमरे में उनकी अस्मत् तार-तार होती थी।

शाम होते बालिका गृह में सजती थी महफिल, बाहरी लोग भी आते थे



किशोरियों को नशे का टैबलेट खिला किया जाता था दुष्कर्म

लड़कियों को नशे का टैबलेट खिलाकर उनके साथ रेप किया जाता था। हाल ही में पुलिस के सर्च ऑपरेशन में बालिका गृह से नशीली दवा के साथ ही अन्य संदिग्ध सामान जब्त किए गए थे। एक पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि बालिका गृह में एक दिन उसे टैबलेट खाने को दिया गया। उसे खाने के बाद वह बेहोश हो गई। जब नींद टूटी तो देखा कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। तब उसे पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है।

गुर्गे पकड़ते थे व संचालक करता था रेप

बालिका गृह में अक्सर शाम होते ही रंगीन महफिल सजती थी। इसमें संचालक के साथ बाहरी लोग भी शिरकत करते थे। शाम 6-7 बजते ही भोजपुरी अश्लील गीतों के बीच लड़कियों को लाया जाता था। फिर संचालक व अन्य की हैवानियत शुरू हो जाती थी। देर रात तक कुकर्म होता था। कोई रोकने-टोकने वाला नहीं होता। आबरू बचाने को लड़कियां रोती-गिड़गिड़ातीं। छोड़ देने की गुहार लगातीं। बेटी की उम्र होने का हवाला देतीं। फिर भी संचालक पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

लड़कियों के कपड़े उतार कर करता था पिटाई

बालिका गृह में लड़कियों को आतंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। दिव्यांग लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया। एक गूंगी लड़की ने इशारों के जरिए दिए बयान में बताया है कि संस्था के हेड सर (संचालक) उसके कपड़े उतार कर पिटाई करते थे। छत पर ले जाकर भी पीटा गया।

'Sex workers won't be criminalised'

cf/ 25-10

WCD Ministry clarifies on the Anti-Human Trafficking Bill passed by Lok Sabha

STAFF REPORTER
NEW DELHI

The Women and Child Development Ministry on Monday sought to defend its Anti-Human Trafficking Bill, and asserted that the proposed law did not criminalise consenting adult sex workers and migrants.

The clarification comes at a time the Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018, is expected to be tabled in the Rajya Sabha after it was passed in the Lok Sabha last week. The Congress and Left parties have demanded that the Bill be put through legislative scrutiny and be sent to a Standing Committee.

"The Bill is clear in excluding consenting adults from its purview. While it criminalises trafficking for the purpose of pushing a woman into sex work, it does not

Maneka says sorry

STAFF REPORTER
NEW DELHI

The Minister for Women and Child Development Maneka Gandhi apologised for using the term "other ones" for transgenders in the Lok Sabha last week during a discussion on the Anti-Human Trafficking Bill.

"I sincerely apologise...I did not "snigger", I was embarrassed at my own lack of knowledge. I was not aware of the official terminology for the transgender community. In future, all official communication will use the term TGs," she tweeted.

punish the act itself. At no point is the victim held as a criminal, or detained against his/ her will...The Bill does not criminalise migration *per se...*," according to a statement issued by the Ministry.

Facing criticism

The proposed legislation has faced criticism from several quarters, including UN experts, for conflating traffick-

ing with sex work and migration.

Maria Grazia Giammarinaro, special rapporteur on trafficking in persons, and Urmila Boola, special rapporteur on contemporary forms of slavery, recently criticised the Bill for addressing trafficking through a criminal law perspective instead of complementing it with a human-rights based and victim-centred ap-

proach. They said that it promoted "rescue raids" by the police as well as institutionalisation of victims in the name of rehabilitation, and that certain vague provisions would lead to "blanket criminalisation of activities that do not necessarily relate to trafficking."

The Ministry maintained that the Bill went beyond legislation and gave "primacy to victims' rights of privacy and dignity", and adhered to various international standards such as the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, the United Nations Office on Drugs and Crime Model Law against Trafficking in Persons, and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking.